ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 414-416

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

निर्धनता उमूलन एवं सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन

मो0 क्यूम
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– राजनीतिशास्त्र विभाग, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया (बिहार), भारत

Received- 27.06.2020, Revised- 29.06.2020, Accepted - 30.06.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***सरकारी नीतियों की वास्तविक गरीबी की समस्या से निपटने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है जैसे बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं– रोजगार बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्राम समृद्धि योजना आदि। इसके अलावा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपाय जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्राथमिक व प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण भवन व सड़क निर्माण, ग्रामीण बिजलीकरण योजनाएं, आधारभूत सुविधाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि। इसके साथ ही, सरकार पिछड़े गरीब, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, भूमिहीन किसान व मजदूरों के कल्याण के विभिन्न प्रयास कर रही है, परंतु वास्तविकता यह है कि गरीब व्यक्ति तक ये सभी सुविधाएं आधी–अधूरी व अपर्याप्त स्थिति में पहुंचती हैं।***

कुंजीभूत शब्द– बेरोजगारी, सरकार, रोजगार बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वरोजगार योजना ।

भ्रष्टाचार, कुसंचालन के कारण बीच के लोग इन योजनाओं को सही व्यक्तियों तक नहीं पहुचने देते व जरूरतमंद गरीब अशिक्षा, अज्ञानता के कारण अभावग्रस्त रहता है। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से कई करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, पूरे एशिया में यह अनुपात बढ़ा है। जिसमें खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से 3.3 अरब की आबादी वाले इस महाद्वीप के करीब 6.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां खाने पर औसतन परिवार 60 प्रतिशत खर्च करता है, वहां गरीबों की स्थिति हाल के वर्षों में दयनीय बनी हुई हैं। यदि भारत में गरीब वर्ग की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट देखें तो सी आई आई रिपोर्ट ऑफ, 2010 CII Report of 2010 (Confederation of Indian Industry Report) के अनुसार मलेरिया, एड्स व टी.बी. जैसी गंभीर बीमारियों से भारत की आबादी के 1.8 करोड़ लोग ग्रसित हैं जिसमें गरीब वर्ग की प्रधानता सबसे ज्यादा है। जिसका असर गैर–संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मानवीय श्रम पर पड़ता है। ये श्रमिक बीमारी में चिकित्सा शुल्क व वेतन ना मिलने या कार्य छूट जाने के कारण और गरीबी का सामना करते हैं। जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव किसी भी देश की आर्थिक उन्नति व उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। रिपोर्ट ने नौ देशों पर सर्वे कर गंभीर परिणामों से अवगत कराया हैं। यह सत्य है कि आज भारत विकास की बड़ी उड़ान भर रहा है व विकास की एक ठोस आशा भी सामने है, परंतु इसमें गरीब व वंचित वर्ग पीछे छूट जाएंगे। सवाल यह उठता है कि उनकी इस विकास यात्रा में कहां और कितने हिस्सेदार रहेंगे क्योंकि भारत की स्थिति अभी तक गरीबों की वास्तविक पहचान करने के तौर–तरीके तय करने में असफल रही है, जबकि सरकारी पैसे को पूरी कुशलता से तय करने, लाभ में बराबर की हिस्सेदारी तथा गरीबी के स्थायी उन्मूलन के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

योजना आयोग हर वर्ष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) हाउसहोल्ड सर्वे आंकड़ों के आधार पर गरीबों के बारे में अकलना करता आया है। आयोग आमदनी के एक निर्धारित स्तर पर गरीबी को रखता है। यानी इतने रुपयों से नीचे की आमदनी वाले गरीब माने जाते हैं तथा गरीबी रेखा, गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों की कैलोरी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है, जैसे 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति ग्रामीण इलाके के लिए तथा 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति शहरी इलाके के लिए तय है।

सारणी–1 दसवीं योजना में गरीबी रेखा से नीचे गरीबी का प्रतिशत

वर्ष	2005	2700
ग्रामीण	28.30	21.7
शहरी	25.70	14.6
संपूर्ण भारत	27.50	19.2

1973–74 से गरीबी रेखा निजी खपत सूचकांक की सीमाओं के आधार पर घटती–बढ़ती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर व विभिन्न राज्यों में गरीबी–रेखा में अंतर है। सन् 2005 में गांवों के लिए यह 365 रुपए और शहरों के लिए 589 रुपए थी। गरीबी की सच्चाई यह है कि गरीबी का स्तर हालांकि कम हो रहा है, लेकिन गरीबों की संख्या लगभग वही है। तभी कहा जाता है कि हिंदुस्तान गरीबों

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

का देश है परंतु गरीब नहीं है। मिक्स रिकॉल पीरियड (MRP) के अनुसार, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी 22 प्रतिशत है। नीति निर्माता, विशेषकर योजना आयेग में बैठे लोग ऐसे अनुमानों का प्रयोग गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए एक कारक के रूप में करते हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि जहाँ केंद्र का प्रयास इन अनुमानों को कम करने का रहता है, वहीं राज्यों का प्रयास रहता है कि इन्हें बढ़ा–चढ़ा कर रखा जाए। आज भी 60 प्रतिशत अनाज लक्षित परिवारों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि राज्य योना आयोग के अनुमानों को रद्द कर अपने अनुमान प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सर्वे डाटा प्रस्तुत करता है, जिसका गरीबों की वास्तविक पहचान से कोई वास्ता नहीं और राज्यों के अनुान प्रत्यक्ष मौखिक जानकारी पर आधारित होते हैं तथा आमदनी पर आधारित मापदंडों से गरीबी का और भी निचला स्तर मिलता है क्योंकि सभी सरकारी आकलन गरीबों की उनकी सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार पहचान नहीं करते है।

यह भी आवश्यक हो जाता है कि किसी भी अनुसंधान से यह अवश्य पता चले कि देश में कितने गरीब हैं, साथ ही गरीब कौन हैं और उनकी पहचान कैसे की जाएं तथा यह भी पहचान हो कि वर्तमान नीतियों के विकल्प में क्या नीतियाँ हों, गरीबों के कल्याण के लिए कौन से कार्यक्रम हों, उन्हें मौजूदा सरकारी ढाँचे और क्षमता के मद्देनजर सबसे निचले स्तर से लागू कैसे किया जाए? यह गरीबी के अनुसंधान को विकेंद्रीकृत करने से संभव हो पाएगा व आकलन व अनुसंधान स्थल को दिल्ली के योजना आयोग से हटाकर राज्यों में ले जाना होगा, ताकि अपने भावी निर्णयों में गरीबों की भी आवाज शामिल हो तथा स्थिति अनुसार उन्हें अपनी गरीबी दूर करने के अवसर भी मिलें। गरीकी की जानकारी उसी जगह के निकट उपलब्ध हो, जहाँ गरीब रहते हैं। मानवीय तौर से गरीबों के कल्याण के लिए यह सबसे लाभ की बात है। परंतु सरकारी योजनाएं अभी तक अतिदीनता की अवस्था को ही दूर नहीं कर पाई। गरीबी हटाने की बात तो दूर की है। दिल्ली जैसे शहर में जहां विभिन्न योजनाएं बनती हैं, वहां 66 प्रतिशत बच्चे जो शहरी झुग्गी–बस्तियों में रहते हैं, कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि आयोजकों ने यह मान लिया है कि विकास विधि द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और सार्वजनिक कल्याण नीतियों के द्वारा गरीबों का जीवन–स्तर उन्नत हो जाएगा। आयोजन की उत्पादन प्रेरक पद्धति, (Production Oriented approach) जिसमें उत्पादन के ढंग को परिवर्तित न किया जाए, का इसके सिवाए और क्या परिणाम हो सकता है कि विकास से लाभ उत्पादन के संसाधन को स्वामी ही हड़प जाएं। पिछली छठी–सातवीं योजना के आयोजकों ने गरीबी–रेखा की धारणा को दीनता (destitution) के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया। जहां पर आयोजकों ने गरीबी को दूर करने के लिए सिंचाई और छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश–कार्यक्रम निश्चित किए, वहाँ वे समृद्धि के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए प्रभावी उचार निर्धारित करने में विफल रहे। आयोजक इस मूल तत्य को समझ नहीं पाए कि विकास व असमानता में कमी दोनों ही व्यापक गरीबी को सफलतापूर्वक दूर करने के लिए अनिवार्य हैं। गरीबी एक बहुआयामी व जटिल समस्या है तथा सभी तथ्य इस बात को ओर संकेत करते हैं कि भारत में निर्धनता देश में चिरस्थायी आर्थिक ढाँचे का परिणाम है, जिसमें आय प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों (Assets) का असमान वितरण विद्यमान है। गरीबी को दूर करने की संस्थानत्मक बीमारी का उपचार करना होगा। अतः बिना समृद्धि के दुश्चक्र को तोड़े गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने का प्रयास संचयी प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डाल सकता, ना ही गरीबों और अमीरों में बढ़ती खाई को पाट सकता है। 'गरीबी हटाओं' जैसे कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए अपूर्ण हैं। गरीबी हटाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के कुवितरण (Maldistributio of fassets) को ठीक करने के लिए सीधा प्रहार किया जाए। यह विषय अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीति–शास्त्र के क्षेत्र का है। अधिकतर गरीबी हटाओ योजनाएं कार्यान्वयन के दौरान विकृत रूप ले लेती हैं। या तो इन्हें छोड़ दिया जाता है या इनके बारे में ढुलमुल नीति अपनाई जाती है। इसके विपरीत मंहगाई व मुद्रास्फीति के कारण समाज का निम्न व मध्यम वर्ग कष्टमय जीवन जी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति की देरों में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिला है। मंहगाई पर काबू पाने के लिए पिछले 13–14 महीनों (2010–11) में रिजर्व बैंक ने 9 बार अपनी ब्याज दरें बढ़ाई है।

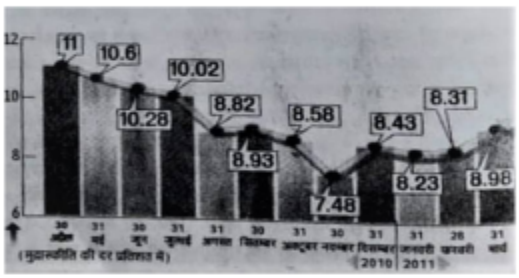

मुद्रस्फीति की दर

RBI Source, 4th April, 2011

श्रमिकों का जीवन स्तर निम्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी–राज्य बीमा योजना, फैक्ट्री अधिनियम

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

आदि होने पर भी श्रमिक इनका भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज भी भारत में 24 प्रतिशत पुरुष व 66 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं तथा दुनिया में पाँच वर्ष से कम उम्र के 37 प्रतिशत शिशुओं की होने वाली मौतों में से आधी भारत में होती हैं। अभी भी देश में कुपोषित शिशुओं की संख्या 83 लाख है जिनमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा मेघालय में हैं। हालांकि भारत में भुखमरी के अनुपात में 2015 तक 17. 6 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है। गरीबी हटाने की कारगर योजनाओं के द्वारा ही इससे निजात संभव है अन्यथा भारत जैसे सफल लोकतंत्र को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य हैं भ्रष्टाचार, संघर्ष व तनाव, प्रशासनिक व शासकीय विफलता, अशांति व अराजकता, सामाजिक अपराधों में बढ़ोत्तरी आदि।

गरीबी हटाने के लिए रोजगार नीति बनाते समय तीन बातें अवश्य ध्यान में रखनी होंगीं। पहली, यह गरीबी व बेराजगारी दूर करने में कारगर होय दूसरी, स्थायी परिसंपत्तियों में तालमेल रखने के साथ–साथ प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा जनसंख्या नीति के लिए परिपूरक हो। हालांकि विभिन्न ग्रामीण व शहरी योजनाएं इसलिए सफल नहीं हो सकीं क्योंकि इनमें कई खामियाँ थी– जैसे गलत लाभांवितों का चुनाव, अपर्याप्त योजना राशि, संसाधनों की निम्न किस्म, अव्यवहारिक कार्यक्रम, घरेलू व स्थानीय मानवीय शक्ति का अभाव व भ्रष्टाचार तथा जवाबदेही की कमी। साथ ही, इन सभी के लिए जिम्मेदार सैद्धांतिक और कार्यान्वयन दोनों दृष्टियों से सरकारी उपायों व कार्यक्रमों में अनेक कमियों रहीं, जिनका उन्मूलन बहुत जरूरी बन जाता है। योजना आयोग का दावा है कि पांच वर्षों में गरीबी में 5 प्रतिशत की कमी आई है तथा विश्व के 124 देशों की खुशहाली का पता लगाने के लिए गैलअप की ओर से कराए गए सर्वे में भारत को 71वाँ स्थान मिला है। यहां केवल 17 प्रतिशत लोग स्वयं को संपन्न मानते हैं तथा 2010 के खुशहाली पर किए गए सर्वे के अनुसार बहुसंख्यक 64 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि वे यहां पर आज भी संघर्षरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Indira Hirway, Baribi Hatao' can IRDP Do it? Economic and Political weekly, March 20, 1985, p.562.
2. Asian Development Bank Report 2011 (ADB), Hindustan Time, 27th April 2011, p.3.
3. CII Report (Confederation of Indian Industry) 2010, published in Hindustan Time, 22th march 2011.
4. अबूसलेह शरीफ, 'गरीबी के शोध की दरिद्रता' Hindustan 27th July 2007. p.10.
5. Santosh Methew and Mark A. Robinson (eds), Economic Reforms and Poverly Reduction, Vikas, New Delhi, 2000, p.11.
6. Rajni Kothari, op. cit. p. 391.
7. World Bandk Repert In ^ Time* 19 May 2011. p. 13.
8. Rao. C.H. Hanumantha and Mahendra Deve, Economic Reforms and Chellenges ahead-An overview, Economic and political Weekly, Special Issue, 2003, March 22-29, app. 1130-41.
9. Rudra Dutt & K.P.M. Sundaram, op. cit., p, 321.
10. Survery. by CRY (Child Rights & You) Hindustan times, 29th April, 2011, p. 10.
11. Sukumar.N. ^State Institution and poverty in India in Contemporary India (Ed) 2010.
12. World Starvation Report* In Hindustan, by International food policy Research Institute, 15th Oct 2007, p. 16.
13. Reserve Bank of India Annual Report, 4th April 2010 in Hindustan times, p. 13.
14. Aggarwal, A.N., op. cit., p. 140.

*****